The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com

नई शिक्षा नीति : 2020 शिक्षा में चुनौतियां एवं नवाचार पर अध्ययन

कंचन जैन
शोधार्थी
शिक्षा विभाग
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सारांश :

शिक्षा राष्ट्र की आधारशिला है क्योंकि यह देश और इसके नागरिकों की वृद्धि और विकास में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पूर्व अध्यक्ष डॉ कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले एक पैनल की सिफारिशों के अनुसार, नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है जो हमारे देश में शिक्षा की इक्विटी, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर केंद्रित है। इस पत्र में, लेखक अन्वेषण करने जा रहा है नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों के बारे में, प्रमुख क्षेत्रों की कमी और इसमें शामिल जटिलताओं के बारे में, यह शोध हाल के डाटा आंकड़ों के साथ-साथ नीति और प्रथाओं के बीच विभाजन पर भी चर्चा करता है। नई शिक्षा नीति में बदलाव के कारण संभावित चुनौतियों से संबंधित सभी विवरणों का विश्लेषण इस पेपर के आगामी खंडों में किया गया है।

कीवर्ड: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, चुनौतियाँ

प्रस्तावना

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आरंभ किया गया है, भारत की नई शिक्षा प्रणाली की दृष्टि को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा है। नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति जारी होने के तुरंत बाद, सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी विशेष भाषा का अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में भाषा नीति एक व्यापक दिशानिर्देश और प्रकृति में सलाहकार है और यह राज्यों, संस्थानों और स्कूलों पर निर्भर है कि वे कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लें। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति का गठन जून 2017 में किया गया था। समिति ने 31 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति शहरी और ग्रामीण भारत में प्रारंभिक और विश्वविद्यालय शिक्षा को शामिल करती है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में 1986 में दूसरी नीति के बाद प्रख्यापित की गई थी।

पहला नई शिक्षा नीति शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों पर आधारित था। इस नीति ने राष्ट्रीय एकीकरण और बेहतर आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को पूरा करने के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली के 'आमूलचूल पुनर्गठन' और सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को समान बनाने की मांग की।

नई शिक्षा नीति ने भारतीय संविधान में वर्णित चौदह वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा को साकार करने का भी आह्वान किया। इसका उद्देश्य उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना भी है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति हैनई शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक विद्यार्थी की रचनात्मक क्षमता के विकास पर बल दिया गया है।

नई शिक्षा नीति 2020 की विशेष विशेषताएं

1.पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।

2.3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;

3.नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4)।

4.व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, 5.कला और विज्ञान के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं।

6.मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।

7.बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; शिक्षा का माध्यम कम से कम 8.ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

9.मूल्यांकन सुधार - किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हों।एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, पारख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना।

10.वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र, शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया, स्कूल परिसरों और क्लस्टरों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

11.राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन।

12.उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना,कई प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र बहुआयामी शिक्षा, एचईआई में प्रवेश के लिए एनटीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की पेशकश करेगा।

13.अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना,

14.बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना।

15.नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना,

16.'लाइट लेकिन टाइट' रेगुलेशन।

17.शिक्षक शिक्षा सहित और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिंगल ओवररचिंग छत्र निकाय- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) -मानक सेटिंग के लिए स्वतंत्र निकायों के साथ- सामान्य शिक्षा परिषद; वित्त पोषण-उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी); मान्यता- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी); और विनियमन- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी);

जीईआर बढ़ाने के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार।

18.शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी।

19. स्टैंड-अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय, या इन या अन्य क्षेत्रों में संस्थान, बहु-अनुशासनात्मक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे।

20.शिक्षक शिक्षा - 4 वर्षीय एकीकृत चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट शिक्षा स्नातक सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।

21.सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण। 100% युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना।

22.नियंत्रण और संतुलन के साथ कई तंत्र उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करेंगे और उसे रोकेंगे। सभी शिक्षा संस्थानों को 'लाभ के लिए नहीं' संस्था के रूप में लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों पर रखा जाएगा। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे।गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान देने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत करना। शिक्षा मंत्रालय: शिक्षा और सीखने पर ध्यान वापस लाने के लिए, MHRD को शिक्षा मंत्रालय (MoE) के रूप में फिर से नामित करना वांछनीय हो सकता है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कमतर माना जाता है। इसलिए, इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सामाजिक स्थिति पदानुक्रम को दूर करना है और चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए, माध्यमिक विद्यालय भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ सहयोग करेंगे। कौशल प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी और स्कूलों में एक हब और स्पोक मॉडल बनाया जाएगा जो अन्य स्कूलों को सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देगा।

प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत और सतत प्रक्रिया है। इस दिशा में वर्तमान में कई पहल की जा रही हैं। समग्र शिक्षा, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्कूली शिक्षा के लिए एक अभिन्न योजना लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में 'विद्यालय' की परिकल्पना करता है। उच्च शिक्षा में भी, विभिन्न योजनाओं, अर्थात्, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पार्क)), ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क (GIAN), इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT), टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (TEQIP), स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (एसडब्ल्यूएवाईएएम), नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम, उच्चतर आविष्कार अभियान, उन्नत भारत अभियान, इंपैक्टफुल रिसर्च इन सोशल साइंसेज (इंप्रेस), अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (एआरआईआईए), नेशनल इंस्टीट्यूशनल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) लागू किया जा रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा भी कई पहल की जाती हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) लागू किया जा रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा भी कई पहल की जाती हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क

(एनआईआरएफ) लागू किया जा रहा है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा भी कई पहल की जाती हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन और कल्पना करता है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

नई शिक्षा नीति 2020 पर रिपोर्ट

पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन के अंतर्गत एक समिति ने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जून 2017 में, एनईपी का मसौदा 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था । नई शिक्षा नीति (डीएनईपी) 2019, बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था , जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए। एनईपी 484 पृष्ठों की थी। मंत्रालय ने नीति तैयार करने में एक कठोर परामर्श प्रक्रिया शुरू की: "2.5 लाख ग्राम पंचायतों , 6,600 ब्लॉकों, 6,000 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), 676 जिलों से दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा *कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को 2022 तक चरणों में लागू किया जाएगा।*

तेलंगाना राज्य सरकार *ने राज्य में नई घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को लागू करने का निर्णय लिया है।*

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे *ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने का निर्देश दिया है.*

आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी *ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राज्य भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू करने का निर्देश दिया है।*

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा *कि एनईपी 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।*

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा *कि NEP 2020 को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा।*

अप्रैल 2022 में, यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) *ने भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में एक साथ दोहरी डिग्री को मंजूरी दी।*

पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल *"निशंक" ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर बात कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणापत्र में नई शिक्षा नीति लाने की जोरदार बात कही*

गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना और भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना था। अब जब नीति आ गई है तो दावा किया जा रहा है कि नीति के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, साथ ही पुरानी नीति में कई संशोधन किए जाएंगे, साथ ही कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी।

नई शिक्षा नीति में चुनौतियां

पहली चुनौती यह है कि देश के शिक्षा क्षेत्र के विशाल आकार और विविधता से उत्पन्न होती है। 1.5 लाख से अधिक स्कूलों, 25 करोड़ छात्रों और 89 लाख शिक्षकों के साथ, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों के साथ इतनी बड़ी शिक्षा प्रणाली में सफलतापूर्वक सुधार करने के लिए हितधारकों के पास निश्चित रूप से उनके लिए काम होगा।

दूसरी चुनौती यह है कि धन की कमी, नौकरशाही और स्कूलों की स्केलिंग और इनोवेशन की क्षमता से जुड़ी है, जैसा कि के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली एनईपी ड्राफ्टिंग कमेटी ने सही बताया है। प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और इन बाधाओं को दूर करने के लिए, मंत्रालय की मौजूदा संगठनात्मक संरचना और इसके पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी।

तीसरी चुनौती यह है कि नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की सफलता केंद्र और राज्य के बीच सफल सहयोग पर भी निर्भर करती है। जबकि एनईपी केंद्र द्वारा तैयार किया गया है, इसकी सफलता राजनीतिक रूप से निष्पक्ष सरकार के समर्थन और सहयोग पर निर्भर करती है।

चौथी चुनौती यह है कि देश के निजी स्कूलों को अपने पक्ष में करना है। यदि सरकार और अन्य नियामक निकाय एनईपी प्रक्रिया में निजी स्कूलों को समान भागीदार के रूप में मान्यता देते हैं, तो वे अति आवश्यक वित्तीय संसाधनों और नवीन तकनीकों के लिए उन पर भरोसा करने में सक्षम होंगे।

पांचवी चुनौती यह है कि नई शिक्षा नीति में विस्तृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, देश के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत प्रशिक्षण और ढांचागत निवेश के लिए आवंटित करना होगा। जबकि यह राशि अकल्पनीय रूप से अधिक लगती है, पचास घंटे के अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) और शिक्षकों के चल रहे प्रशिक्षण के लिए शासन और निवेश दोनों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत होती है।

नई शिक्षा नीति में नवाचार

नई शिक्षा नीति 2020 साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षकों के लिए सहायक के रूप में सेवा करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और शिक्षकों और छात्रों के बीच मौजूद किसी भी भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए प्रायोगिक और कार्यान्वित किया जाएगानई शिक्षा नीति 2020 में सभी स्थानीय और भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद (आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता) का उपयोग करके, सभी स्तरों पर छात्रों के लिए

आनंददायक और प्रेरणादायक पुस्तकें विकसित की जाएंगी, और इन्हें बेहतर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल और स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालयों दोनों में बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता।

नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी और नवाचार की मदद से, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) और राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा और भारत में उन युवाओं की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूत किया जाएगा जो सक्षम नहीं हैं। एक भौतिक स्कूल में भाग लेने के लिए।

नई शिक्षा नीति 2020 में सीखने के परिणामों की उपलब्धि में अंतर को बंद करने के लिए, कक्षा-संचालन योग्यता-आधारित शिक्षा और शिक्षा की ओर स्थानांतरित होगा।

बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, सभी भाषाओं के शिक्षण को अभिनव और अनुभवात्मक तरीकों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, जिसमें गेमिफिकेशन और ऐप के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं - जैसे कि फिल्म, थिएटर, कहानी, कविता और संगीत में बुनाई शामिल है।

नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह, चयनित विश्वविद्यालयों जैसे, दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से उन विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य एसईडीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य इनोवेशन को बेहतर बनाना और कोर्सों की संख्या और प्रकार को बढ़ाना है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े व्यवसायों के लिए, गणित और गणितीय सोच के साथ अच्छी तरह से वाकिफ होना बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए गणित और कम्प्यूटेशनल सोच पर पूरे स्कूल के वर्षों में अधिक जोर दिया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के नवीन तरीकों के माध्यम से शुरू होता है। .

नई शिक्षा नीति इस तथ्य पर अधिक जोर देती है कि उच्च शिक्षा को ज्ञान सृजन और नवाचार का आधार बनना चाहिए जिससे बढ़ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान हो। इसका परिणाम अधिक उत्पादक, नवोन्मेषी, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र होगा।

उच्च शिक्षा संस्थान स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे; प्रौद्योगिकी विकास केंद्र; अनुसंधान के सीमांत क्षेत्रों में केंद्र। एचईआई छात्र समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र और प्रतियोगिताओं का विकास करेगा। यह 100% साक्षरता हासिल करने के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए वयस्क शिक्षा के लिए मजबूत और अभिनव सरकारी पहलों को सक्षम करेगा।

यह नीति एचईआई के संकाय को नवीन शिक्षण, अनुसंधान और सेवा का संचालन करने का अधिकार देती है, जैसा कि वे सबसे अच्छा देखते हैं। यह वास्तव में उत्कृष्ट, रचनात्मक कार्य करने के लिए उनके लिए एक प्रमुख प्रेरक और

सक्षम करने वाला होगा। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, संस्थानों और संकाय के पास उच्च शिक्षा योग्यता के व्यापक ढांचे के भीतर पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के मामलों में नवाचार करने की स्वायत्तता होगी।

वर्तमानकालीन समय में भारत में अनुसंधान और नवाचार निवेश, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.8%, इज़राइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.69% है। आज के समय में भारत जिन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता आदि से निपटने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ एक शीर्ष स्तरीय विज्ञान की आवश्यकता है।

किसी भी देश की पहचान, उत्थान, आध्यात्मिक/बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता भी उसके इतिहास, कला, भाषा और संस्कृति के माध्यम से प्रमुख रूप से प्राप्त होती है। इसलिए, कला और मानविकी में अनुसंधान, विज्ञसामाजिक विज्ञान में नवाचार के साथ, एक राष्ट्र की प्रगति और प्रबुद्ध प्रकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारत में वास्तव में गुणवत्ता अनुसंधान को विकसित करने और उत्प्रेरित करने के लिए, यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की कल्पना करती है, जो अकादमिक संस्थानों में, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में, जहां अनुसंधान वर्तमान में एक प्रारंभिक अवस्था में है, उत्कृष्ट अनुसंधान को मान्यता और समर्थन देगा। ऐसी संस्थाओं की सलाह। एनआरएफ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी विषयों में अनुसंधान को निधि देगा।

इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर आदि।

उपसंहार

एक कुशल कार्यान्वयन एक नीति को बहुत बड़ा बना सकता है। सफलता और दूसरी ओर, यदि कार्यान्वयन अच्छा नहीं है, तो यह बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। समीक्षा पत्र एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा करता है। जमीनी हकीकत यह है कि सबसे महत्वपूर्ण 3 स्तंभ- अवसंरचना, वित्त पोषण और एक विस्तृत योजना रणनीति अभी भी गायब है। इस समीक्षा पत्र में कई अन्य कारकों पर चर्चा की गई है और प्रत्येक कारक अपने आप में वास्तविक है। गुड्स एंड बैड्स का विश्लेषण इंगित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

(29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं: स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे" । हिंदुस्तान टाइम्स । 30 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त

जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020)। "द हिंदू एक्सप्लेन्स | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है?" . द हिंदू । आईएसएसएन 0971-751X । 2 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

विश्नोई, अनुभूति (31 जुलाई 2020)। "एनईपी '20: एचआरडी के साथ अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्देश माध्यम में कोई बदलाव नहीं" । द इकोनॉमिक टाइम्स । 31 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

गोहेन, मानश प्रतिम (31 जुलाई 2020)। "एनईपी भाषा नीति व्यापक दिशानिर्देश: सरकार" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 31 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020)। "समझाया: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना" । द इंडियन एक्सप्रेस । 2 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

चतुर्वेदी, अमित (30 जुलाई 2020)। "'परिवर्तनकारी': नेता, शिक्षाविद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं । हिंदुस्तान टाइम्स । 30 जुलाई 2020 को पुनः प्राप्त किया गया । जबकि अंतिम नीति की घोषणा 1992 में की गई थी, यह अनिवार्य रूप से 1986 की एक पुनरावृत्ति थी।

"कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाला पैनल स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम विकसित करेगा" । indianexpress.com. 22 सितंबर 2021 . 16 अक्टूबर 2021 को पुनःप्राप्त ।

"राज्य शिक्षा बोर्डों को राष्ट्रीय निकाय द्वारा विनियमित किया जाएगा: मसौदा एनईपी" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 21 नवंबर 2019 को पुनःप्राप्त । "यहां बताया गया है कि आप नए एनईपी पर क्यों खुश हो सकते हैं। और आप क्यों नहीं कर सकते" । द वायर । 31 जुलाई 2020 । 2 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

जेबराज, प्रिसिला; हेब्बर, निस्तुला (31 जुलाई 2020)। रमेश पोखरियाल निशंक कहते हैं, "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने से पहले कठोर परामर्श किया गया" । द हिंदू । आईएसएसएन 0971-751X । 2 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त रोहतगी, अनुभा, सं. (7 अगस्त 2020)। "हाइलाइट्स | एनईपी भारत में अनुसंधान और शिक्षा के बीच की खाई को कम करने में भूमिका निभाएगी: पीएम मोदी" । हिंदुस्तान टाइम्स । 8 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

"सरकार ने शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी" । लाइवमिंट । 29 जुलाई 2020 । 30 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दी मंजूरी: मुख्य बिंदु" । टाइम्स ऑफ इंडिया । 29 जुलाई 2020 । 29 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

"कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 10 अंक" । एनडीटीवी डॉट कॉम । 30 जुलाई 2021 को पुनःप्राप्त ।

"कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी, देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त" । पीआईबी.जीओवी.इन । 8 अगस्त 2021 को पुनःप्राप्त ।

"शिक्षा मंत्रालय ने निपुन भारत मिशन की शुरुआत की" । @बिजनेसलाइन । 8 अगस्त 2021 को पुनःप्राप्त ।

श्रीनिवासन, चंद्रशेखर, एड. (29 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति, NEP 2020: कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण: नई शिक्षा नीति पर 10 बिंदु" । एनडीटीवी । 29 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

कुलकर्णी, सागर (29 जुलाई 2020)। "नई नीति स्कूली शिक्षा के 5-3-3-4 मॉडल की पेशकश करती है" । डेक्कन हेराल्ड । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

कुमार, शुचिता (31 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति: 10+2 से 5+3+3+4 प्रणाली में बदलाव" । टाइम्स नाउ । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

"वर्ष में दो प्रयासों के साथ आसान बोर्ड परीक्षा: एचआरडी ने मसौदा शिक्षा नीति में सुझाव दिया" । इंडिया टुडे । प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यू. 4 नवंबर 2019 । 31 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

THE RESEARCH DIALOGUE
Manifestation Of Perfection

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-January-2023/08

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

कंचन जैन

For publication of research paper title

नई शिक्षा नीति : 2020 शिक्षा में चुनौतियां एवं नवाचार पर अध्ययन

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-04, Month January, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com